कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम (छ.ग.)

Phone 07741-232895, Fax No- 07741-232987, E-Mail : zp-kawardha.cg@nic.in

क./3263 /अमृतकाल@ 2047"/ 2024 कबीरधाम दिनॉक 11/06/ 2024

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य नीति आयोग नीति भवन सेक्टर–19
कैपिटल कॉम्पलेक्स नवा रायपुर अटल नगर

विषय– **"अमृतकाल": छत्तीसगढ़ विजन @ 2047" विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में जिला स्तरीय विजन संबंधी सुझाव के संबंध में।**

संदर्भ– आपका पत्र क्रं. 1449/एन–02/अमृतकाल@2047/2024 दिनांक 20.06.2024.

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु की गई परिकल्पना को साकार करने के लिये जिले के विभिन्न विभाग प्रमुखों से **"अमृतकाल": छत्तीसगढ़ विजन** @2047" संबंधित विजन डॉक्यूमेंट का लेख किया गया है। जिसमें जिले के विभिन्न सेक्टरों हेतु संभावनाएँ, फोकस एरिया एवं लघु (5 वर्ष), मध्यम (10 वर्ष), दीर्धकाल (25 वर्ष), के लिए एक्शन पाईंट का चिन्हांकन हेतु सुझाव लिया गया है।

अतः प्राप्त सुझाव आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कलेक्टर,
जिला कबीरधाम छ.ग.

पृ. क./3264/अमृतकाल@ 2047"/ 2024 कबीरधाम दिनॉक 11/06/ 2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, योजना एवं सांख्यिकीय, नीति भवन सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, पंचायत संचालनालय विकास भवन भू–तल सेक्टर 19 नार्थ ब्लाक नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक सह नोडल, योजना एवं सांख्यिकीय ब्लाक 02 भू–तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ ओर सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर,
जिला कबीरधाम छ.ग

अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन / 2047 विजन

कबीरधाम जिले के विभागों से विजन @47 विजन के संभावनाएं एवं सुझाव

क्रं.	विभाग का नाम	लघुकाल 5वर्ष	मध्यकाल 10वर्ष	दीर्घकाल 25वर्ष
1	2	3	4	5
1	(वन, जलवायु एवं परिवर्तन विभाग) वृक्षारोपण	कवर्धा वनमंडल कुल क्षेत्रफल 4447.00 वर्ग कि.मी. है जिसमे से 1103.00 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है अर्थात कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत वनक्षेत्र है ऐसे मे वन बाहय वृक्षो का महत्व बढ़ जाता है अतः वन बाह्य क्षेत्रो मे नागरिको को जागरुक कर तथा स्कूल कॉलेज अन्य संस्थानो का चयन कर हरियाली के क्षेत्र को बढावा देना।	उद्योग मे उपयोग आने वाले प्रजाति के वृक्षारोपण एवं अर्बन वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ताकि आम जनता को इसका लाभ मिले।	उक्त योजना के क्रियान्वयन से आम जनता को पर्याप्त हरियाली एवं रोपित किये गये पौधो जो वृक्ष के रुप मे तैयार हो गये हो उसका लाभ आम जनता को उपलब्ध कराना।
	जल संवर्धन	कवर्धा वनमंडल मे स्थित अधिकांश नरवा का उत्थान कार्य कराया गया है जिसे ट्रीटमेंट कर उनके वाटर लेबल को बढ़ाना होगा।	नरवा में वाटर लेबल बढ़ने पर उक्त जल स्त्रोत का उपयोग मानव एवं वन्यप्राणियों के जनजीवन के उत्थान में उपयोग हेतु समुचित व्यवस्था बनाना।	नरवा का सम्पूर्ण विकास होने के पश्चात संचित जल से लाभकारी योजना तैयार कर उसका लाभ आम जनता को उपलब्ध कराना।
	ऑनलाईन नीलाम व्यवस्था	कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत वनोपज को नीलाम की व्यवस्था आनलाईन करना।	आनलाईन व्यवस्था से अधिक से अधिक लोगो को नीलाम में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना।	आनलाईन व्यवस्था से देश स्तर पर वनोपज का अच्छा मूल्य ब्रिकी से प्राप्त होगा। जिससे प्रदेश का राजस्व वृद्वि कराया जाना।
	मिलेट	कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत वनक्षेत्र मे निवास कर रहे पट्टाधारी व्यक्तियो को मोटे अनाज कोदो, कुटकी, रागी सिघाड़ा एवं तिखुर इत्यादि के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना।	मिलेट अनाज के उपयोग से होने वाले लाभ से आम जनता को प्रचार–प्रसार कर अवगत कराना तथा उसकी बिक्री के लिए बाजार मे समुचित व्यवस्था करना।	मिलेट अनाज के उत्पादन एवं प्रर्दशन से इसका लाभ दीर्घकाल मे प्राप्त होगा इनमे पोषक तत्वो तत्वो के रुप मे कार्बोहाइड्रेट, मैग्निशियम, प्रोटीन, मैग्निज, कैल्शियम, थायामिन, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, फाइबर एवं रिबोफ्लेमिंग प्रचुर मात्रा मे पाये जाते है, जो कि आधुनिक जीवन शैली मे मधुमेह, कार्डियोरेस्कुलर, वजन घटाने मे, कैंसर मे , लीवर एवं किडनी मे एंटीमाइक्रोबियन इत्यादि बिमारियो के लिए लाभप्रद है।
	शहद प्रसंस्करण कार्य	बोड़ला मे संचालित शहद प्रसंस्करण केन्द्र मे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा शहद प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है जिसकी संरचना का विकास/ प्रशिक्षण/ मार्केट लिंकेज एवं बार्डिग का कार्य किया जाना है	शहद प्रसंस्करण केन्द्र का समावेशी विकास, उत्पादन को 4 गुना बढाना तथा वेश्वीक पहचान करना	शहद प्रसंस्करण केन्द्र से उत्पादित शहद को बाजार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रो मे शहद का विक्रय करना ताकि आम जनता को शुद्ध शहद छत्तीसगढ़ स्तर पर उपलब्ध कराना।

क्रं.	विभाग का नाम	लघुकाल 5वर्ष	मध्यकाल 10वर्ष	दीर्घकाल 25वर्ष
1	2	3	4	5
	माहुल पत्ते का प्रसंस्करण	वन क्षेत्र में उपलब्ध माहुल पत्तों से दोना पत्तल इत्यादि तैयार करने का केन्द्रो की स्थापना ।	राज्य स्तर पर तैयार किये जा रहे माहुल पत्तों से दोना पतलों का बाजार स्थापित करना।	जिले में इसके उपयोग को पूर्ण रूप से बढ़ावा देकर प्लास्टिक मुक्त करना ।
	लघु वनोपज	कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत वनक्षेत्र मे निवास कर रहे पट्टाधारी व्यक्तियो को लघु वनोपज के उत्पादन के संबंध मे जागरुक करना तथा चार, चिरौंची, मशरुम, लाख एवं मुनगा इत्यादि के उत्पादन बढ़ावा देना।	लघु वनोपज के उत्पादन से मिलने वाले लाभ के संबंध मे वनवासियो को अवगत कराते हुए उसके लाभ को उन्हे दिलाने की समुचित व्यवस्था कर लाभ दिलाने।	लघु वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा देने पर इसका दीर्घकालिक लाभ वनवासियो एवं आम जनता को पोषटीक आहार उपलब्ध होगा। वनमंडल क्षेत्र मुनगा उत्पादन हेतु उपयुक्त है जिसका पाउडर दवा के रुप मे लाभकारी है।
	जंगल सफारी की स्थापना	भोरमदेव अभ्या. क्षेत्र को जंगल सफारी के रूप में विकसित करना।	आम जनता को जंगल सफारी का भ्रमण एवं उसके लाभ के बारे में प्रचार प्रसार कर गेट मनी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से शासन को आय मिलने की व्यवस्था करना।	उक्त योजना को पर्यटन के रूप में देश स्तर पर प्रसारित करना।
2	खनिज विभाग	जिले के मैदानी क्षेत्र मुख्यतः सहसपुर लोहारा व कवर्धा तहसील में अच्छी किस्म के चूनापत्थर एवं डोलोमाईट उपलब्ध है। हमारे द्वारा उक्त क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी उत्खनिपट्टा हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जा रहा है। निकट भविष्य में उत्खनिपट्टा स्वीकृति से प्राप्त होने वाले राजस्व से जिले की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी साथ ही साथ लोगों को व्यापार व अन्य आधारभुत संरचनाओं की प्राप्ति होगी। खनन से प्रभावित क्षेत्रों में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सकता है तथा मृदा अपर्दन, वायु की गुणवत्ता, इत्यादि में भी सुधार होगा।	जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टों के अवसान उपरांत उक्त उत्खनित स्थलों पर अधिकांशतः जलाशय बनाया जाना प्रस्तावित है। कलस्टर में अवस्थित खदानों से निर्मित होने वाले जलाशयों को आपस में मिला कर बृहद् जलाशय में तब्दील किया जा सकता है। जिसमें विभिन्न प्रकार वाटर स्पोर्ट जैसे कि बोटिंग, स्कूबा, पैरासेलिंग इत्यादि का आयोजन किया जा सकेगा। जिससे लोगों को रोजगार तथा मनोरंजन दोनो की प्राप्ति होगी। जलाशय निर्मित हो जाने से आस–पास के लोगों को निस्तारी व सिंचाई हेतु जल सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। जिससे विभिन्न प्रकार खेती की जा सकेगी। जो लोगों के आर्थिक उत्थान सहयोगी सिद्ध होगा साथ ही साथ जलाशयों में मछली पालन की भी प्रचूर संभावनायें है। जलाशयों में जल को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। इसके साथ भूजल संवर्धन भी होगा जिससे पेय जल संकट जैसी समस्या को दूर किया जा सकेगा तथा जलस्तर के सुधार होने से खेती व अन्य उपयोगों के लिए भी लाभप्रद होगा।	जिले में उपलब्ध मुख्य खनिजों को देखते हुए मुख्य खनिज लौह अयस्क, बॉक्साईट एवं चूनापत्थर के दोहन के लिए विभिन्न क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जावेगा। जिससे निवेशक बृहद मात्रा में उद्योग व अन्य चिजों के लिए सहज ही आकर्षित होंगे जिनमे से मुख्यतः सिमेंट प्लांट लौह एवं एल्युमिनियम से संबंधित उद्योग प्रमुख होंगे। जिले में संभावित खनन/उद्योगों से प्राप्त राजस्व एवं अन्य क्षेत्र से लोगों के आने से पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में पर्यटन की अपार सभावनाएं है पठारी क्षेत्र होने के कारण मानसून व शीत काल में मौसम अत्यधिक रमणिक हो जाता है। इसी प्रकार उक्त क्षेत्रों में पर्यटन हेतु आधारभूत संरचनाओं के सृजन करने से जिले को अलग पहचान प्राप्त होगी। जिले के पठारी क्षेत्रों में खनिजों के दोहन पश्चात् उक्त भूमि पर विभिन्न स्तरों में समतलीकरण किये जाने से खेती, बागवानी, वनकीकरण के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा, जिससे आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण में मदद होगी।

क्रं.	विभाग का नाम	लघुकाल 5वर्ष	मध्यकाल 10वर्ष	दीर्घकाल 25वर्ष
1	2	3	4	5
3	शिक्षा विभाग	विजन @47 में शिक्षा समुन्नयन हेतु शत् प्रतिशत शून्य अप्रवेशी दर व शून्य शाला त्यागी दर करना, शिक्षकों एवं छात्रों की जानकारी पोर्टल में नियमित अद्यतन करना है। सभी बच्चों का युनिक आई.डी जारी करना है। स्कूल एवं कार्यालय में रिक्त पदो की पूति तथा नई शिक्षा–नीति प्रारंभ कर अध्ययन–अध्यापन चालू करना। कौशल–केन्द्रित शिक्षा, विषय शिक्षा आदि हेतु विशेष प्रयास करना। जिले के आवासीय खेल परिसर में खेल विशेषज्ञ की पदस्थापना एवं सेटअप के साथ समुचित संचालन। एकलब्य विद्यालय सुदृढीकरण, कन्या शिक्षा परिसर का सुदृढीकरण तथा जॉब ओरिएंटेड व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में शैक्षिक संस्थान का संचालन करना।	समस्त विद्यालय व कार्यालयों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना। हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी शाला में AI प्रारंभ करना। समस्त जिले में पीपीपी मॉडल के अनुसार सहयोग से केन्द्रीयकृत रसोई घरो की व्यवस्था करना जिससे सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त भोजन मिल सके। हाई एवं हायर सेकेण्डरी शाला के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों की लगातार परामर्श व सेमिनार तथा केरियर मार्गदर्शन। कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु AI एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित करना तथा वनांचल क्षेत्र में सैनिक स्कूल की स्थापना, नवीन आश्रम शालाओं का विस्तारिकरण कर समुचित उन्नयन करना। वनांचल क्षेत्र के विद्यालयों को इन्सेटिब्स के साथ स्थानीय मानक भाषा का शिक्षा में समुचित उपोग कर बेहतर संचालन।	जिले के सभी शालाओं के सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाना। उपग्रह लिकिंग प्रणाली के तहत सभी स्कूलों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर अध्ययन–अध्यापन कराना। सभी स्कूलों में AI प्रणाली के माध्यम से शिक्षा जिसमें मानव शिक्षकों के साथ'– साथ रोबोट शिक्षको का भी प्रयोग। विश्व के श्रेष्ठ स्कूलों के साथ जिले के स्कूलों का लिंकअप जिससे श्रेष्ठतम अध्यापकों का लाभ सेटेलाईट के माध्यम से बच्चों को प्राप्त हो। बच्चों में आंत्र प्रेन्योर शिप विकसीत करना व उन्हे वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करना। डिजिटाईजेशन डिस्ट्रिक्ट डाटा कम काल सेन्टर के रूप में कम्प्यूटर एज्युकेशन सेंटर कबीरधाम का स्ट्रेनथनिंग एण्ड अपग्रेडेशन।
4	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना । जिला अस्पताल में सिटी स्कैन, ब्लड कम्पोनेट की सेवाऐं प्रारंभ करना। जिले की 50 प्रतिशत संस्थाओं को NQAS प्रमाणीकरण करना। शत्–प्रतिशत टीकाकरण, ए.एन.सी. पंजीयन एवं संस्थागत प्रसव का लक्ष्य प्राप्त करना। जिले की 75 प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाओं को सौर पैनल की सुविधा उपलब्ध करना। बोडला एवं पण्डरिया विकासखण्ड में 10 स्वास्थ्य संस्थाओं में बर्थ प्रतीक्षालय कक्ष की स्थापना करना। विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं(स्वास्थ्य शिक्षा, वॉलीटियर आदि) का संवर्धन करना। एनिमिया की जॉच के लिए हीमोग्लोबिनो मीटर की उपलब्धता समस्त उपस्वास्थ्य केन्द्रों में सुनिश्चित करना।	समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा की पदस्थापना, SNCU, C- Section, Blood bank की सुविधा प्रारंभ करना। DH में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा प्रारंभ करना। जिले की 100 प्रतिशत संस्थाओं को छफौ प्रमाणीकरण करना। जिले की 100 प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाओं को सौर पैनल की सुविधा उपलब्ध करना।	हृदय घात एवं आपातकीन सेवाएं के लिए ऐयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना। DH में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रारंभ करना।

क्रं.	विभाग का नाम	लघुकाल 5वर्ष	मध्यकाल 10वर्ष	दीर्घकाल 25वर्ष
1	2	3	4	5
5	महिला एवं बाल विकास विभाग	राष्ट्रीय पोषण अभियान के लक्ष्यों के अनुरूप प्रति वर्ष कुपोषण की दर में 2 प्रतिशत की कमी लाने हेतु जिले में संचालित 1706 आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक बच्चें के पोषण स्तर का गहन अनुश्रवण करना । जिले में वर्तमान कुपोषण की दर 15 प्रतिशत को अगली 5 वर्ष में पोषण अभियान के लक्ष्य के अनुरूप कम करने सतत् प्रयास करना, इस हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) को विशेष रूप से फोकस करना। सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्यों की सुरक्षा क मानको का पालन कर सभी को पोषण आहार से लाभान्वित करना। शत प्रतिशत हितग्राही दर्ज कर शासन की योजनाओ का लाभ दिलाना। प्राथमिकता से मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना जैसे भवन, शौचालय,पेयजल,विद्युत,उपकरण एवं पृथक से रसोई घर की व्यवस्था आदि। ECCE गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाना। महिला बाल विकास की गतिविधियों आंगनबाडी केन्द्र की सेवाओं के उन्नयन मे Artificial intelligence (AI) को बढ़ावा देना।	सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वय के भवन हो, बच्चों हेतु नर्सरी स्कूल के तर्ज पर केन्द्रों में सुविधा, रंगरोगन, यूनिफार्म आदि की व्यवस्था हो। सभी केन्द्रो में अतिरिक्त कक्ष तथा कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की व्यवस्था हो। आंगनबाड़ी केन्द्रो में प्री स्कूल गतिविधियों हेतु आवश्यक संसाधन जैसे स्मार्ट टी.वी. व अन्य खिलौनों का विस्तार हो जिससे बच्चों में रूचि बढ़े एवं उनका मानसिक विकास हो। वर्तमान में कुपोषण की दर में लगातार कमी आ रही है अतः पोषण आंगनबाड़ी हेतु द्वितीयक विषय बन जाएगा एवं समय के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं के दृष्टिकोण में बदलाव होगा एवं बच्चों का संपूर्ण विकास, महिलाओं का क्षमता वर्धन ही प्राथमिकता में होगा। अतः महिलाओं के संगठन शक्ति को उचित दिशा देने आंगनबाडी केन्द्रो को बहुउद्देशीय गतिविधियों अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र के रूप में भी स्थापित करना।	1. आंगनबाड़ी केन्द्रो का ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित किया जानाः– ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों हेतु प्रमुख है प्रत्येक सप्ताह पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी 2–3 घंटे के सत्र का आयोजन से पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध में जनजागरूकता लाना। केन्द्रो में संसाधनों की पूर्ति एवं उनका क्षमता वर्धन किया जाना आवश्यक है। स्वं सहायता समूह की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाए जाने संसाधन केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिससे नवीन व्यवसाय की स्थापना, चुनौतियों का निराकरण, रोजगार परामर्श शिविरों का आयोजन आदि कियाा जा सकता है। 2 आंगनबाड़ी केन्द्रो में मूलभूत सुविधाओं का विस्तारः–सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रामिकता से मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना जैसे भवन, शौचालय,पेयजल,विद्युत,उपकरण एवं पृथक से रसोई घर की व्यवस्था आदि। 3. एक समान ड्रेसः–सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की समानता के दृष्टिकोण से सभी बच्चों हेतु गणवेश, प्री स्कूल बैग, जूते–चप्पल, पानी की बॉटल उपलब्ध होने से बच्चों में समानता की भवना विकसित करना तथा अपने समान के प्रति रखरखाव की जिम्मेदारी का बोध कराना। 4. प्री स्कूल की गतिविधियों में सुधार हेतु क्षमता वर्धनः– आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्री स्कूल संबंधी गतिविधियों में क्षमता वर्धन अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक संसाधनो एवं प्रशिक्षणों के सहयोग से गतिविधियों को रोचक तथा अन्य भिन्नता बनाए रखने हेतु निरंतर क्षमतावर्धन किया जाना आवश्यक है।
6	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) एवं जल संसाधन विभाग (WRD)	नलकूप स्त्रोत पर आधारित योजनाओं का रिचार्ज स्ट्रक्चर तैयार करना। ग्राम स्तरर पर भूजल स्तर उचित रख रखाव के लिए ग्राम के आसपास नाला, नदी में छोटे–छोटे जल संवर्धन के कार्य कराते हुए स्त्रोत भण्डारण हेतु योजना तैयार करना। मृत पड़े हुए नलकूप को रिचार्ज करने हेतु रिजार्जिग स्ट्रक्चर तैयार करना।	छीरपानी जलाशय योजना नहर विस्तीकरण से 1900 हैक्टर में सिंचाई सुविधा उत्पन्न होगी तथा नहर के तटस्थ ग्रामों में भू–जल स्तर की वृद्धि होगी एवं मिट्टी में नमी बनी रहने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा।	विकासखण्ड स.लोहारा में नीर लघु जलाशय का निर्माण कार्य करने से 12 MCM का जल संग्रहण किया जाएगा तथा सिंचाई हेतु 1854 हेक्टर की सुविधा उत्पन्न की जाएगी। तथा फीडर चैनल निर्माण कर पण्डरिया के सूखे क्षेत्र में जल की आपूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार करना है।

क्रं.	विभाग का नाम	लघुकाल 5वर्ष	मध्यकाल 10वर्ष	दीर्घकाल 25वर्ष
1	2	3	4	5
7	(कृषि एवं अन्य संबंधित विभाग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2.0)	वर्तमान में जिले में दो वाटरशेड परियोजना संचालित है, जो कि पर्याप्त नहीं है, प्रथम पॉच वर्ष में सभी विकासखण्ड में अर्थात चार परियोजना की आवश्यकता है।	अगले दस वर्षो में यह परियोजना सभी तहसील (8) में संचालित होनी चाहिए	परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले कार्यो जैसे – चेक डेम, डबरी, सोख्ता, स्टॉप डेम, परकोलेशन टेंक इत्यादि का प्रभाव इन वर्षो में देखने को प्राप्त होगा। जैसे – जलस्तर में वृद्धि, सिंचाई सुविधा का विस्तार, पीने का स्वच्छ पानी इत्यादि।
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना	वर्तमान में चेम्प्स योजना के माध्यम से बीज निगम द्वारा संचालित हो रही है, जिसके कारण स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं विद्युत पंप तथा समस्त प्रकार के कृषि यंत्रो के उठाव/वितरण में कमी आयी है। यह योजना अगर कृषि विभाग से संचालित हो तो उपरोक्त यंत्र के उठाव होने से कृषकों के संसाधन में वृद्धि होगी।	वर्तमान में चेम्प्स योजना के माध्यम से बीज निगम द्वारा संचालित हो रही है, जिसके कारण स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं विद्युत पंप तथा समस्त प्रकार के कृषि यंत्रो के उठाव/वितरण में कमी आयी है। यह योजना अगर कृषि विभाग से संचालित हो तो उपरोक्त यंत्र के उठाव होने से कृषकों के संसाधन में वृद्धि होगी।	इसका प्रभाव दीर्घ काल में देखने को प्राप्त होगा वर्तमान परिववेश में कृषि मजदूर की समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि संसाधन को बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक है। इस हेतु उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्र की उपयोगिता आवश्यक है, जिससे फसलों के बुवाई से लेकर कटाई तक के उपकरण उपलब्ध होने से कृषकों की समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा
	मिलेट मिशन योजना	वर्तमान में मोटे अनाज (कोदो, कुटकी एवं रागी) की खेती 17550 हेक्ट मे की जा रही है, मिलेट मिशन योजना अंतर्गत प्रदर्शन एवं प्रचार–प्रसार कराया जाकर 5 वर्षो में इसे 20000 हेक्ट. तक करने से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।	मिलेट मिशन योजना अंतर्गत मोटे अनाज (कोदो, कुटकी एवं रागी) प्रदर्शन का आयोजन कर एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम से 10 वर्षो में 25000 हेक्ट. तक करने से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। लघु धान्य फसलों में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौष्टिक गुण समाहित है।	मिलेट मिशन अंतर्गत मोटे अनाज (कोदो, कुटकी एवं रागी) को प्रदर्शन एवं प्रचार–प्रसार कराया जाकर 25 वर्षो में इसका प्रभाव दीर्घ काल में देखने को प्राप्त होगा एवं उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इनमें पोषक तत्वों के रूप में कार्बोहाइड्रेट, मैग्निशियम, प्रोटीन, मैग्निज, कैल्शियम, थायामिन, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, फाइबर एवं रिबोफ्लेमिंग प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं, जो कि आधुनिक जीवन शैली में मधुमेह, कार्डियोरेस्कुलर, वजन घटाने में, कैंसर में, लीवर एवं किडनी में, एंटीमाइक्रोबियल इत्यादि बिमारियों के लिए लाभप्रद है।

क्रं.	विभाग का नाम	लघुकाल 5वर्ष	मध्यकाल 10वर्ष	दीर्घकाल 25वर्ष
1	2	3	4	5
8	क्रेडा, विभाग	• जिला कबीरधाम कृषि प्रधान जिला है यहां लगभग 1.69 लाख पंजीकृत किसान है जो कि गन्ना,धान गेंहूं इत्यादि का उत्पान करते हैं एवं जिसमें से 30से 35 प्रतिशत किसान सिचांई हेतु बिजली पंप या डीजल पंप का उपयोग करते है। को आगामी 05 वर्षों में सोलर पंप से प्रस्थापित कर भूमिगत जल एवं परम्परागत विद्युत की बचत की जा सकती है।	इसमें मुख्य उद्देश्य सोलर ड्यूल पंप संयंत्रो की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्रो में पूर्व में स्थापित सार्वजनिक बोर में सबमर्सिबल पंप की स्थापना कर सोलर पंप संचालित किया जाता है तो 40 से 50 घरो में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। सोलर पंप के उपयोग एवं आवश्यकता के आधार पर 06 मी., 09मी., एवं 12मीटर के सोलर ड्यूल पंप स्थापना किया जाता है इसके लिए जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं एवं अन्य औद्यौगिक संस्थाओं से प्राप्त राशि से किया जा सकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के चौक–चौराहों में सोलर हाई मास्ट का स्थापना कार्य किया जा सकता है। जहां पर प्रकाश की व्यवस्था में कठिनाई या अधिक व्यय करना पड़ता है सोलर हाई मास्ट के माध्यम से प्रकाश किया जा सकता है। सोलर हाई मास्ट में एक उॅचा 09 मी.के पोल निर्धारित क्षमता के पैनल, एल.ई.डी. लाईट, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी कन्ट्रोलर एवं वायररोप सह चैन पुल्ली लगे होते है। रात्रि में निर्बाध प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिले के सभी विकासखंड में स्थापित किया जा सकता है।	जिला कबीरधाम अंतर्गत् कुल 468 ग्राम पंचायत एवं 1006 ग्राम है। यदि ऐसे ग्राम जहां सी.एस.पी.डी.सी.एल. का ग्रिड उपलब्ध हो ऐसे ग्रामों में ग्राम पंचायत में स्थापित ट्रासंफार्मर के क्षमतानुसार ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र का स्थापित करना जिससे कि दिन में बिजली की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
9	जिला व्यापार एवं उद्योग	जिले में कृषि उत्पाद जैसे धान, गन्ना, कोदो का उत्पादन अधिक मात्रा मे होता है, अतः कृषि से संबंधित उद्योग जैसे राईस मिल, गुड़ उद्योग, कोदो प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना प्रस्तावित है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके।	जिले के प्रत्येक विकासखंड कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला एवं स.लोहारा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर उद्योग स्थापना हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ताकि अधिक से अधिक उद्योग इकाई की स्थापना सरलतापूर्वक की जा सके।	कृषि एवं वन उत्पाद का संरक्षित भंडारण हेतु जिले में वेयरहाउस एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक उत्पाद का परिहन हेतु लाजिस्टिक पार्क (हब) का विकास करना प्रस्तावित है, ताकि उत्पाद का विक्रय हेतु बाजार का वृहद् क्षेत्र उपलब्ध हो सके।
	जिला कौशल विकास प्राधिकरण	जिले में उपलब्ध शासकीय एवं अशासकीय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष संभावित 1000 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जावेगा। इसी प्रकार 5 वर्ष में 5000 एवं 25 वर्ष में 25000 युवा/युवतियों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगारमुखी कार्यक्रम राज्य व केन्द्र से प्राप्त महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लक्ष्यपूर्ति किया जायेगा।	जिले में गुड उद्योग के आवश्यकता को देखते हुए गुड निर्माण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस हेतु 5 वर्षो में 500 एवं 25 वर्षो में 12000	केन्द्र सरकार की योजना सूर्य मित्र अंतर्गत जिले में 5 वर्ष में 500 हितग्रहियों को सोलर पेनल हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। 25 वर्ष में 12500 हितग्रहियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
10	ई–गर्वनेश, संचार	प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिजिटल आईडी, आपदा और महामारी से सचेत करने की प्रणाली, ई कार्यालय की स्थापना एवं विशेषकर दूरदराज के इलाकों में उपलब्धता के अनुसार बेहतर मोबाईल और इंटरनेट कनेक्टिविटी।	बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल विलेज की स्थापना। ऑनलाईन पेंमेट को बढ़ावा देना। सभी पुराने रिकॉर्ड का डिजिटाईजेशन ।	डिजिटल आई.डी. को सभी विभाग के सेवाओं को जोड़ना।

क्रं.	विभाग का नाम	लघुकाल 5वर्ष	मध्यकाल 10वर्ष	दीर्घकाल 25वर्ष
1	2	3	4	5
	नगर तथा ग्राम निवेश	विभाग द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्र एवं उसके आस–पास के ग्रामों को निवेश क्षेत्र में शामिल किया जाकर विकास योजना तैयार किया जाता है। योजना का मूल उद्देश्य शहरों का सुनियोजित विकास होता हैं तथा विकास योजना का क्रियान्वयन नगर विकास योजना के माध्यम से किया जाता है। विकसित कवर्धा हेतु नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे जिसमें नगरीय निकायों हेतु एजेंसी नियुक्त किया जावे, जिससे विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग, आमोद–प्रमोद क्षेत्र, खेल मैदान, सड़को पर प्रकाश व्यवस्था, जल निकास, मल प्रवाह का विकास सुनियोजित रूप से किया जा सके। जिले के आम–जन के मन एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुये कबीरधाम जिले के शहर का मास्टर प्लान तैयार कर विकसित शहरों की तर्ज पर आगे बढ़े।	विभाग द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्र एवं उसके आस–पास के ग्रामों को निवेश क्षेत्र में शामिल किया जाकर विकास योजना तैयार किया जाता है। योजना का मूल उद्देश्य शहरों का सुनियोजित विकास होता हैं तथा विकास योजना का क्रियान्वयन नगर विकास योजना के माध्यम से किया जाता है। विकसित कवर्धा हेतु नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे जिसमें नगरीय निकायों हेतु एजेंसी नियुक्त किया जावे, जिससे विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग, आमोद–प्रमोद क्षेत्र, खेल मैदान, सड़को पर प्रकाश व्यवस्था, जल निकास, मल प्रवाह का विकास सुनियोजित रूप से किया जा सके। जिले के आम–जन के मन एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुये कबीरधाम जिले के शहर का मास्टर प्लान तैयार कर विकसित शहरों की तर्ज पर आगे बढ़े।	विभाग द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्र एवं उसके आस–पास के ग्रामों को निवेश क्षेत्र में शामिल किया जाकर विकास योजना तैयार किया जाता है। योजना का मूल उद्देश्य शहरों का सुनियोजित विकास होता हैं तथा विकास योजना का क्रियान्वयन नगर विकास योजना के माध्यम से किया जाता है। विकसित कवर्धा हेतु नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे जिसमें नगरीय निकायों हेतु एजेंसी नियुक्त किया जावे, जिससे विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग, आमोद–प्रमोद क्षेत्र, खेल मैदान, सड़को पर प्रकाश व्यवस्था, जल निकास, मल प्रवाह का विकास सुनियोजित रूप से किया जा सके। जिले के आम–जन के मन एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुये कबीरधाम जिले के शहर का मास्टर प्लान तैयार कर विकसित शहरों की तर्ज पर आगे बढ़े।
	नगरी निकाय	चूंकि नगरीय निकाय क्षेत्र में बिजली सप्लाई हेतु सोलर Energy के द्वारा सप्लाई की तैयारी हेतु आगामी समय मे Fund की आवश्यकता पड़ेगी। (Implementation & Mangement)	आगामी वर्षो में नगर पालिका का रूपान्तरण नगर निगम के रूप में होगा, जिसमें लिये बाहय वृद्धि क्षेत्र में Infrastructure development एवं mMangement & maintainance की आवश्यकता रहेगी। इसके लिये निर्माण एवं Maintainace हेतु funds की आवश्यकता पड़ेगी। i.) SWM वै के अन्तर्गत आगामी वर्षो में नगर निगम में परिवर्तन होने पर Door to Door waste collection हेतु 170 कर्मचारी की आवश्यकता होने की संभावना है। ii.) वर्तमान में कवर्धा शहर में 13 वर्षो से निकलने वाले दूषित जल की Treatmetn हेतु 2.1 MLD की STP बना हुआ है आगामी वर्षो में शेष वार्डो के लिये 5.0 MLD के STP की आवश्यकता पड़ेगी।	जल प्रदाय में वर्तमान में नगर पालिका कवर्धा द्वारा वर्ष 2047 तक Supply का design है। आगामी वर्षो में आसपास की पंचायतों को छोड़कर नगर निगम की सीापना किये जाने पर उन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु जल आवर्धन के तहत शामिल किये जाने पर अतिरिक्त fund की आवश्यकता पड़ेगी। इससे नगरीय क्षेत्र में शुद्ध जल (पेयजल) की आपूर्ति होगी।